

person—Netaji Subhash Chandra Bose—and particularly his achievement in national unity. On 23rd January, 1948, that is, the birthday of Netaji Subhash Chandra Bose, he made a speech. In that speech I quote Mahatma Gandhi saying "I have never observed the birthday of my own or of anybody, but today I am observing the birthday of Netaji Subhash Chandra Bose for the particular reason that the way Netaji achieved national unity cutting across the barriers of caste, creed, religion, region and language and for that reason I command the whole country to emulate the example for the achievement of national unity". In view of that feeling of Mahatma Gandhi, will the Government consider the 23rd January of the coming year, that is, 1979, as a national unity day for emotional integration of the people of India ?

SHRI MORARJI DESAI : As the hon. Member himself has said that it is a sensitive question, I do not want to make it more sensitive and I am afraid I cannot agree with the hon. Member's proposal.

PROF. SAMAR GUHA : It is not a sensitive one in this country. Nobody can say that. He is the only one man who achieved the national unity, he is the only one man who cut cross the barriers of religion, caste creed, etc. It is only he who showed the Hindus, the Muslims and the Christians to shed blood together and on that basis India achieved unity. It is for that reason that I would say that this is a fit occasion to declare that day as national unity day for the emotional integration of the Indian people.

MR. SPEAKER : This is question Hour. No more supplementaries by you, please.

PROF. SAMAR GUHA : I would make an appeal and request him to consider it.

श्री कंबरलाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने यह मीटिंग बुलाई बहुत सालों के बाद, और उसमें एक छोटी कमेटी बनाई जोकि इस बारे में रिकमेंडेशन देगी कि किस तरह से इंटिग्रेशन होना चाहिए। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि चूंकि यह मामला बहुत अरजेंट है, कई जगहों

पर देश में कम्युनल रायट्स हुए हैं जोकि नहीं होने चाहिए थे, हम उसकी निन्दा करते हैं और पूरा इंटिग्रेशन होना चाहिए लेकिन कमेटी द्वारा रिकमेंडेशन देने में कुछ देर हो सकती है और जब तक रिकमेंडेशन नहीं आती है तब तक मामला अरजेंट होने की वजह से आप इमीजिएटली क्या कदम उठा रहे हैं ? क्या आप यह भी कर रहे हैं कि स्कूल कालेजों में इंटिग्रेशन के बारे में लड़कों को एजुकेशन दी जाये।

SHRI MORARJI DESAI : That requires more careful consideration I cannot do it tomorrow.

डा० रामजी सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छी बात है कि प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रीय एकता समिति की अनिवार्यता को समझा है। 1970 के बाद कभी इसकी बैठक नहीं हुई है। मैं जानना चाहता हूँ नेशनल इंटिग्रेशन काउंसिल की सदस्यता और उसके पुनर्गठन के विषय में भी क्या वे कुछ सोच रहे हैं ताकि नयी परिस्थिति के सन्दर्भ में उसका ठीक से पुनर्गठन किया जा सके और वह सशक्त हो सके ?

श्री मोरारजी देसाई : कांग्रेस में जो कमेटी बनाने का फैसला किया गया वह कमेटी बनने के बाद बराबर इस पर सोच रही है—यह मैंने कहा है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन को गिरिडीह से कलकत्ता स्थानान्तरित करना

* 427. **श्री रामदास सिंह :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन सांख्यिकी विभाग को गिरिडीह से कलकत्ता स्थानान्तरित करने के बारे में सरकार ने निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है; और

(ग) यदि नहीं तो साठ रिक्त पदों को मुख्यालय में अन्तरित करने का आदेश दिये जाने के क्या कारण हैं ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) There is a Data Processing Centre of the Data Processing Division of the National Sample Survey Organization at Giridih. No decision has been taken to shift this Centre to Calcutta.

(b) Does not arise.

(c) Only 34 posts have been transferred from Giridih to Calcutta/Delhi as they were found surplus to the requirements in Giridih on account of abandonment of two tabulator units.

श्री रामदास सिंह : अध्यक्ष महोदय गिरिडीह से दो टेबुलेटर मशीन कलकत्ते ले जाई गई हैं, इसी कारण वहां के स्टाफ को कलकत्ता भेजा गया है। कहा जाता है कि वहां काम ज्यादा नहीं था, यदि सरकार गिरिडीह में ही इन को रहने देती तो इस में खर्च भी कम पड़ता, साथ ही व्यवस्था भी ठीक से होती, चूंकि गिरिडीह त्रैकवर्ड ऐरिया है, वहां के लोग एम्प्लायमेंट चाहते हैं, एम्प्लायमेंट की दृष्टि से भी उचित था कि उन को वहीं रहने दिया जाता। मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूँ—क्या जिन 2 मशीनों तथा 56 पोस्ट्स को गिरिडीह से कलकत्ता भेजा गया, उन को फिर गिरिडीह वापस करेंगे ताकि वहां की स्ट्रेन्थ भी ठीक हो जाय और वहां का काम भी ठीक से चले ?

श्री मोरारजी देसाई : 56 पोस्ट्स नहीं भेजी गई, 34 भेजी गई हैं और वह भी इस लिये कि वहां काम नहीं था, व लोग काम के बगर बैठे थे, क्योंकि

वहां मशीनों को सुधारने का काम नहीं हो सकता था। चूंकि वहां लोग बेकार बैठे थे, काम नहीं होता था, इस लिए जो लोग भेजे गये उन की मर्जी से, उन की सहमति से भेजे गये, उन की मर्जी के खिलाफ नहीं भेजे गये हैं।

श्री रामदास सिंह : अध्यक्ष महोदय जब अपनी मर्जी से किसी आदमी का ट्रांसफर होता है, तो पोस्ट का भी ट्रांसफर किया जाना जरूरी नहीं होता है। कलकत्ता जो लोग जाते हैं, उन को 15 परसेन्ट हाउस रेंट और 6 परसेन्ट सिटी एलाउन्स देना पड़ता है, इस का अर्थ है बैसन का 21 परसेन्ट ज्यादा देना पड़ता है, जो खर्च के लिहाज से भी सरकार को वहां ज्यादा पड़ता है। जो पोस्ट्स वहां भेजी गई हैं, वे भी षडयन्त्र कर के भेजी गई हैं, कुछ खास लोग जिन को अधिकारी वर्ग वहां ले जाना चाहते थे, भेजे गये हैं। सरकार के किसी भी कारपोरेशन में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई व्यक्ति ट्रांसफर होना चाहे तो उस को उस की पोस्ट के साथ ट्रांसफर किया जाय, व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन पोस्ट को ट्रांसफर नहीं करना चाहिये था। मैं इन सब मुद्दों पर प्रधान मंत्री जी का स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य ने जो कहा है, उस दलील के साथ मैं सहमत नहीं हूँ। यह बात नहीं है कि कुछ खास अधिकारियों ने ऐसा किया है ! अगर जैसा मैंने कहा है—वहां काम नहीं था, काम हो नहीं रहा था, काम कि बगर लोग वहां पर थे, इस लिये वहां से भेजना पड़ा। वहां पर वे काम कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि वहां पर मशीनों की दुस्ती का काम नहीं

हो रहा था, उस के लिए मशीनों को कलकत्ता या दूसरी जगहों पर भेजना पड़ता था, इसी लिये वहां काम होना सम्भव भी नहीं था ।

ऐसी बात नहीं है कि वहां काम है, फिर भी भेजा गया है ।

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : मैं आप के माध्यम से प्रधान मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ—बिहार में, खास कर दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर कमिश्नरी और संथाल परगना में जो पब्लिक अण्डरटेकिंग के उद्योग धन्धे चल रहे हैं उन के कार्यालयों को कलकत्ता भेजा जा रहा है, उन के कर्मचारियों को कलकत्ता भेजा जा रहा है इस प्रकार की आशंका व्याप्त है । क्या प्रधान मंत्री जी इस आशंका को दूर करने के लिये कोई उपाय निकालेंगे ।

श्री मोरारजी देसाई : आशंका सही हो, तो मैं दूर कर सकता हूँ, लेकिन आशंका कल्पित हो तो कसे दूर करें ?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूँ यदि वहां पर कर्मचारी अधिक हो गये थे और अपनी मर्जी से उन्होंने स्थानान्तरण पसन्द किया, तो उन्हें टी० ए० और डी० ए० भत्ता क्यों दिया गया ? जो अपनी मर्जी से जाना है उसको टी० ए० और दूसरा भत्ता नहीं दिया जाता है ।

गिरिडीह बिहार का सब से पिछड़ा हुआ जिला है । वहां पर पदों को ही स्थानान्तरित कर दिया गया है । व्यक्ति को तो स्थानान्तरित किया जा सकता है लेकिन पद को कैसे किया जा सकता है ;

उन लोगों को जो नाजायज भत्ता और टी० ए० आदि दिया गया है, जब कि वे अपनी मर्जी से गये थे, क्या वह उचित था ?

श्री मोरारजी देसाई : भत्ता दिया गया तो वह नाजायज कैसे दिया गया यह मेरी समझ में नहीं आता है । जब ट्रांसफर करना होता है और ट्रांसफर किया जाता है तब उनकी सहमति है । इसलिए उनको भत्ता न दिया जाए यह बात मेरी समझ में नहीं आई है । नाजायज कैसे हुई यह चीज ? यह उलटी बात हो रही है ।

Updating of Technology of Automobile Industry

*428. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the Planning Commission is keen on the updating of technology of the automobile industry keeping in view the economy in the consumption of fuel ; and

(b) if so, the details regarding the scheme of Government in this regard ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) and (b). The Working Group on Transport, Earth Moving Equipment and Agricultural Machinery set up by the Planning Commission to formulate programmes of development for the Five Year Plan period 1978-83, has submitted its recommendations recently. The recommendations cover the main sectors of the automotive industry including commercial vehicles, passenger cars, two-wheelers, tractors, earth-moving equipment etc. Various studies, including those based on the recommendations of the Working Group, are in progress for updating the automotive industry including improvement of fuel efficiency of passenger cars.

श्री ईश्वर चौधरी : जन उपयोग की दृष्टि से हमारे यहां जो यातायात के साधन हैं उन में जो ईंधन लगता है, अभी तक देखा गया है कि साइकिल को छोड़ कर बाकी सब खर्चीले हैं ।